ISSN: 3048-9423(Online)
Naveen International Journal of Multidisciplinary Sciences (NIJMS)
© NIJMS | Vol. 2 | Issue 1 | August-September 2025
Available online at: https://nijms.com/
DOI: https://doi.org/10.71126/nijms.v2i1.92

दूरस्थ शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की चुनौतियाँ: वैचारिक अंतर्दृष्टि

राहुल यादव [1] एवं डॉ० देवेंद्र कुमार यादव [2]

[1] शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

[2] सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

[1]Corresponding Author Email: yesiamrahulyadav@gmail.com

शोध सारांश:

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना केवल शैक्षिक नीतियों का प्रश्न नहीं बल्कि एक मज़बूत प्रशासनिक ढाँचे और प्रशासकों का भी उत्तरदायित्व होता है तथा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा इस लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है किंतु इसके समुचित संचालन और व्यवस्थापन में अनेक प्रशासनिक बाधाएँ सामने आती हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य इन्हीं चुनौतियों की पहचान करना और उनके समाधान हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना है। इस लेख में द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जो विभिन्न ऑनलाइन प्रति स्रोतों से संकलित है, साथ ही साथ शैक्षिक प्रशासन और नेतृत्व से संबंधित पूर्ववर्ती शोधों को आधार बनाया गया है। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के सुचारु संचालन में प्रमुख अवरोधों जैसे प्रशासनिक समन्वय का अभाव, तकनीकी संसाधनों और संयोजकता की कमी, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, शिक्षार्थी सहायता सेवाओं की कमजोरी, शिक्षार्थियों की प्रतिधारण क्षमता में गिरावट, कार्यभार की अधिकता, शिक्षार्थी सहभागिता में कमी, वित्तीय और नियामक संस्थाओं एवं तकनीकी अवसंरचना (ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, वर्चुअल कक्षाएँ, डिजिटल कंटेंट और मूल्यांकन प्रणाली) को पर्याप्त रूप से विकसित न कर पाना एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरता है। परिणामस्वरूप मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रभावित होती है तथा शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के बीच असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। यह कहा जा सकता है कि यदि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की प्रशासनिक संरचना को पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाए तो इन चुनौतियाँ को अवसरों में परिवर्तित किया जा सकता हैं, जिससे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्रभावी नेतृत्व, सतत प्रशिक्षण, वित्तीय अनुशासन, प्रौद्योगिकी का स्थायी उपयोग और विद्यार्थी-केंद्रित नीतियों को अपनाकर इस शिक्षा प्रणाली को अधिक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और परिणामोन्मुख बनाया जा सकता है एवं शिक्षा अपने वास्तविक उद्देश्यों को सर्वसुलभ और समावेशन द्वारा प्राप्त करने में सफल सिद्ध होगी।

मुख्य शब्द : *प्रशासनिक चुनौती, शिक्षार्थी प्रबंधन चुनौती, प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचा, संकाय कर्मचारी प्रबंध।*

1. परिचय:

राष्ट्रीय कर्तव्यों में प्रथम कर्तव्य उस देश के प्रत्येक नागरिक की ज्ञान-पिपासा को शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना तथा एक उत्कृष्ट शैक्षणिक ढाँचे का निर्माण करना है। लेकिन यह कार्य जितना ही सहज और सुव्यवस्थित प्रतीत होता है यह उतना ही अधिक समस्यात्मक और चुनौतीपूर्ण है। इस जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य को सरल एवं प्रभावी बनाने में शिक्षा व्यवस्था की विभिन्न संरचनाएँ अपना योगदान देती हैं, जिनमें

प्रशासनिक संरचना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा की पूरी प्रणाली का संचालन पर्यवेक्षण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आधारशिला इसी प्रशासनिक ढाँचे पर आधारित होती है। किसी भी संस्था चाहे वह निजी हो अथवा सार्वजनिक, राष्ट्रीय हो या स्थानीय का सफल संचालन एक सुदृढ़, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था के बिना संभव नहीं है। शैक्षिक प्रशासनिक संरचना उन नीतियों, प्रक्रियाओं, संस्थागत व्यवस्थाओं और मानव संसाधनों का समुच्चय है जिनके माध्यम से प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक का संगठन, प्रबंधन और मूल्यांकन किया जाता है। इसका कार्य केवल योजनाएँ बनाना या आदेश जारी करना भर नहीं बल्कि शिक्षक-नियुक्ति, प्रशिक्षण, संसाधनों का वितरण, पाठ्यचर्या निर्धारण, छात्रवृत्ति प्रबंधन, मूल्यांकन पद्धति तथा संस्थागत उत्तरदायित्व तक फैला हुआ है परंतु व्यवहार में यह संरचना अनेक चुनौतियों से घिरी हुई है। प्रशिक्षित शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी, डिजिटल संसाधनों का अभाव, अपर्याप्त प्रशिक्षण, समन्वयहीनता, कमजोर शिक्षार्थी सहायता सेवाएँ, गुणवत्तानियंत्रण की शिथिलता और प्रभावी प्रतिक्रिया-तंत्र का न होना ये सभी शिक्षा की कार्यकुशलता को बाधित करते हैं।

आधुनिक समय में जब शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिगत अधिकार और जीवन-निर्माण का आधार माना जा रहा है तब एक सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना का अभाव शिक्षा की गुणवत्ता, पहुँच और उपयोगिता तीनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता प्रतीत हो रहा है। और यह प्रक्रिया तब और अधिक क्लिष्ट हो जाती है जब राजनीतिक हस्तक्षेप, विकेंद्रीकरण की विसंगतियाँ तथा नीतियों के असंगत क्रियान्वयन इस व्यवस्था के अपना स्थान बना लेता है। इसलिए शिक्षा प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दक्षता-आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा सतत् प्रशिक्षण को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना आवश्यक है। स्पष्ट है कि यदि शैक्षिक प्रशासनिक ढाँचे में मानव एवं तकनीकी संसाधनों की पूर्ति कर नीतिगत एवं क्रियान्वयनात्मक सुधार लाए जाएँ तो शिक्षा वास्तव में लोकतांत्रिक, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बन सकेगी। इन्हीं सब चुनौतीपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त शोध पत्र को लेखबद्ध किया गया है।

2. साहित्य समीक्षा:

2.1 शिक्षा- शिक्षा का संबंध ज्ञान अर्जन, प्रशिक्षण और व्यक्तिगत विकास से है ताकि वह व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में समान और सकारात्मक योगदान दे सके। शिक्षा में न केवल स्कूली और औपचारिक अनुभव शामिल हैं बल्कि अप्रत्यक्ष, आकस्मिक और अनौपचारिक प्रभावों को भी शामिल किया जाता है जो शिक्षार्थियों को सीखने में किसी न किसी रूप में सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे प्रभाव और गतिविधियाँ हमारे चरित्र, व्यवहार और धारणाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इसलिए शिक्षा को एक सक्षमकारी माध्यम के रूप में देखा जाता है। जिसके द्वारा लोग अपनी क्षमताओं से भली भांति परिचित हो सकें और एक उत्पादनशील नागरिक के रूप में राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे सकें।

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा व्यवस्था से है जो पूर्ण रूप से किसी भी तरह के प्रतिबंधों से मुक्त होती है। और शिक्षार्थियों को उसके दुर्गम से दुर्गम निवास स्थान पर भी उसकी सुविधा को देखते हुए प्रदान की जाती है। ताकि राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय विश्वास की भावना से प्रत्येक नागरिक ओत-प्रोत होकर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें।

2.2 प्रशासन- साधारण शब्दों में यदि प्रशासन को समझने का प्रयास किया जाए तो प्रशासन संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था, निगरानी, नियोजन तथा आयोजन करने का कार्य है। प्रशासन किसी संगठन के उद्देश्यों को साकार करने के लिए मानव और भौतिक संसाधन दोनों को एक साथ लाने की व्यवस्थित प्रक्रिया है तथा संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में संगठनात्मक संसाधनों का अनुप्रयोग और परिनियोजन है। प्रशासन से संबंधित अनेक वक्तव्यों में कुछ ने व्यक्त मतानुसार जिनमें ड्वाइट वालन ने यह कहा है कि प्रशासन केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि यह एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो जनसेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी होती है। इसी तरह एम.पी.शर्मा के अनुसार प्रशासन लोकनीति को कार्यरूप में लागू करने वाला तंत्र है तथा यह सरकार का कार्यकारी अंग है। इन मतावलंबियों के मत से यह विदित होता है कि वास्तव में शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासन बहुत प्रासंगिक है। शिक्षा प्रणाली की सफलता काफी हद तक

शैक्षणिक प्रशासन पर निर्भर करती है। शिक्षकों, शिक्षार्थियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और संसाधनों की कुशलतापूर्वक व्यवस्थित निगरानी और नियंत्रण किया जाना चाहिए ताकि वे शैक्षणिक योजना के अनुसार सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम कर सकें जिससे प्रशासनिक संरचना को और भी सुदृढ़ किया जा सके।

2.3 शैक्षिक प्रशासन- शैक्षिक प्रशासन शिक्षा के लिए उपलब्ध मानव एवं भौतिक संसाधनों और कार्यक्रमों की व्यवस्था और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनका व्यवस्थित उपयोग करना है। और यह संभवतः संभव तब है जब किसी भी पद पर आसीन प्रशासक इसको एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तौर पर इस का निर्वाहन करता हो। किसी भी व्यवस्था या पद्धति में अनिवार्य रूप से विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का आयोजक और कार्यान्वयनकर्ता होता है जो संपूर्ण संरचना को विभिन्न पदानुक्रमों में विभाजित कर उच्च से निम्न की ओर क्रियान्वित करता है। **बुश (2007)** ने अपने लेख में बताया है कि शैक्षिक प्रशासन केवल संगठनात्मक ढाँचे तक सीमित नहीं है बल्कि नेतृत्व सिद्धांतों और नीतियों से गहराई से जुड़ा है। **हॉलिंगर और हेक (1996)** ने विद्यालय प्रशासन में प्रधानाध्यापक की भूमिका और उसके शैक्षणिक परिणामों पर प्रभाव का विश्लेषण किया है। **लेथीवुड और जानतज़ी (2000)** का अध्ययन दिखाता है कि प्रशासनिक नेतृत्व शैली छात्रों की भागीदारी और संस्थागत माहौल को कैसे प्रभावित करती हैं। **क्यूबान (1988)** ने अपने शोध में प्रशासनिक प्रबंधन और नेतृत्व के बीच संतुलन की चर्चा की। **ओवेन्स और वालेस्की (2014)** की पुस्तक विद्यालय संगठनात्मक व्यवहार और प्रशासनिक सुधार पर गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। **होय और मिस्केल (2012)** का क्लासिक ग्रंथ प्रशासनिक सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग पर आधारित है। **मॉर्फी (1990)** ने प्रशासनिक नेतृत्व और पाठ्यचर्या प्रबंधन की भूमिका को विस्तार से समझाया है। **फॉरेस्टोन और रिहेल (2005)** का लेख शैक्षिक प्रशासन में भविष्य के शोध एजेंडा की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इन सभी पूर्वर्ती अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि शैक्षिक प्रशासक किसी न किसी रूप में नियोजन, नीति निर्माण और कार्यक्रम निर्माण में योगदान दे सकता है फिर भी उसकी प्रमुख भूमिका शिक्षा के लाभ के लिए ऐसी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में निहित है, जिसमें कई प्रक्रियाएं शामिल हैं जैसे योजना बनाना, समन्वय करना, नियंत्रण करना और अन्य प्रबंधन प्रक्रियाओं में शामिल होना और नीतियों के निर्माण में योगदान देना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक संगठन का प्रमुख विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों की सावधानीपूर्वक योजना बनाता है। ये शैक्षिक संगठन एक स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय हो सकते है। प्रमुख इन कार्यक्रमों और गतिविधियों को अन्य शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों के सहयोग से आयोजित करता है, प्रेरित करता है, स्टाफ सदस्यों के प्रयासों का समन्वय, उन पर नियंत्रण और निर्देशन भी रखता है। प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने में कर्मचारियों के प्रदर्शन और प्रगति का मूल्यांकन करता है, प्रतिक्रिया प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर संस्थान की योजनाओं और कार्यक्रमों में संशोधन भी लाता है। इन प्रक्रियाओं की समग्रता जो शिक्षण संस्थाओं के उद्देश्यों को साकार करने या प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित होती है शैक्षिक प्रशासन कहलाती है।

3. मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की मुख्य प्रशासनिक चुनौतियां:

3.1 शिक्षार्थी प्रबंध चुनौतियां- शिक्षार्थी प्रबंधन एक ऐसी सुव्यवस्थित शैक्षिक गतिविधि है जिसके माध्यम से शिक्षक अथवा शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों के आचरण, आवश्यकताओं, रुचियों और सीखने की गति को संतुलित और नियंत्रित रूप में दिशा प्रदान करते हैं। इसका प्रमुख ध्येय कक्षा या विद्यालय में ऐसा वातावरण निर्मित करना है जो न केवल अनुशासित हो बल्कि छात्रों को प्रोत्साहित करने वाला और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुकूल भी हो। यह प्रक्रिया मात्र अनुशासन बनाए रखने तक सीमित नहीं रहती बल्कि विद्यार्थियों के मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक पक्षों का समन्वित एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करती है। विद्यार्थी प्रबंध में चुनौतियों को कुछ मुख्य बिंदुओं द्वारा दर्शाया गया है जो इस भांति हैं।

3.1.1 शिक्षार्थी प्रतिधारण- किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित विद्यार्थी अपने सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की अवधि तक उसी संस्थान से जुड़े रहें और उसे पूर्ण करें यही संस्थान और शिक्षार्थी दोनों का उद्देश्य होता है। किंतु वास्तविक स्थिति में अनेक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक अथवा व्यक्तिगत कारणों से अनेक विद्यार्थी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं या बीच में ही किसी अन्य संस्था की ओर रुख कर लेते हैं। जो उनकी दुर्बल प्रतिधारण क्षमता को प्रदर्शित करती है और यह शिक्षार्थी के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है।

3.1.2 तकनीकी विभाजन संलग्नता- तकनीकी संसाधनों जिनमें कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन तक समान रूप से पहुँच न होना और सूचना व संचार तकनीक का प्रभावी उपयोग न कर पाना। यह असमानता ओपन एवं डिस्टेंस शिक्षा में छात्रों की सहभागिता और सफलता के लिए इन्हें एक गंभीर चुनौती के रूप में स्वीकारा गया है।

3.2 तकनीकी बुनियादी ढांचा- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा में तकनीकी बुनियादी ढांचा वह संगठित प्रणाली है जिसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुविधाएँ, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, शैक्षिक सामग्री प्रबंधन तंत्र और तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन सम्मिलित होते हैं। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें वर्चुअल कक्षा-कक्ष, मूक आदि इसी तरह के और भी ऑनलाइन शिक्षण मंचों को सम्मिलित किया जाता है। संचार साधन जिसमें इंटरनेट, मोबाइल एप्स, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सामग्री प्रबंधन जिसमें ई-लाइब्रेरी, ई-बुक्स, ऑडियो-वीडियो व्याख्यान, इंटरैक्टिव कंटेंट आदि को स्थान प्राप्त है। मानव संसाधन तकनीकी में सहायक, प्रशिक्षित शिक्षक, और डिजिटल समर्थन सेवाएँ आदि आती हैं। इस क्षेत्र में आने वाली प्रमुख चुनौतियां मुख्यतः इस प्रकार हैं।

3.2.1 संयोजकता- संयोजकता का शाब्दिक अर्थ होता है तेज़, स्थिर, सुरक्षित और निरंतर डेटा संचार की सुविधा का होना। किसी उपयोगकर्ता डिवाइस या नेटवर्क का वैश्विक सूचना तंत्र अर्थात् इंटरनेट से जुड़ने और डेटा का आदान-प्रदान करने की क्षमता के संदर्भ में संयोजकता को जाना जाता है। जो सभी नेटवर्क जाल को आपस में सहसमबद्ध रखने का प्रयास करता है और इसी के अभाव में इसे एक चुनौती पूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया जाता है।

3.2.2 प्लेटफ़ॉर्म विखंडन- तकनीकी क्षेत्र में प्लेटफ़ॉर्म विखंडन किसी डिजिटल सेवा सॉफ़्टवेयर या हार्डवेयर के भिन्न संस्करणों, रूपों अथवा मानकों का मौजूद होना। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लिकेशन संस्करणों के बीच परस्पर संगतता और समानता बाधित होती है। ऐसी स्थिति उपयोगकर्ता अनुभव को असमान बनाती है तथा डेवलपर्स और संगठनों के लिए विकास प्रक्रिया और सिस्टम एकीकरण को जटिल कर देती है। जिससे शिक्षार्थी और शिक्षण संस्थान दोनों के लिए यह एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। जिससे कि शैक्षणिक क्रियाकलाप में एक बाधा उत्पन्न होती है और उपयोगकर्ताओं के लिए एक चुनौती भी।

3.3 संकाय प्रबंधन- किसी शैक्षणिक संस्थान में संकाय सदस्यों (शिक्षक, प्रोफेसर, शोध मार्गदर्शक) तथा प्रशासनिक-अकादमिक सहायक कर्मचारियों के कार्यों की प्रभावी योजना, संगठन, निर्देशन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और समन्वय की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संस्थान की शैक्षिक गतिविधियों का सुचारु एवं गुणवत्तापूर्ण संचालन सुनिश्चित किया जाता है। इसमें आने वाली प्रमुख चुनौतियों में इन्हें सम्मिलित किया गया है।

3.3.1 प्रशिक्षण- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की सफलता बड़े पैमाने पर उसके प्रशासनिक तंत्र की दक्षता पर निर्भर करती है किंतु इस क्षेत्र में एक प्रमुख चुनौती कर्मचारियों और सहायक स्टाफ के अपर्याप्त प्रशिक्षण की है। जब प्रशासनिक, तकनीकी और शैक्षणिक कर्मचारी आधुनिक तकनीकों, ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म, मूल्यांकन प्रणालियों तथा छात्र सहयोग सेवाओं का पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो इससे शिक्षा-प्रक्रिया की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जिससे प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग, प्रशासनिक कार्यों में विलंब, विद्यार्थी सहयोग सेवाओं में कमजोरी तथा गुणवत्ता और विश्वसनीयता में कमी देखने को मिलती है।

3.3.2 कर्मचारी कार्यभार- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में कर्मचारियों (शिक्षक, ट्यूटर, समन्वयक, तकनीकी स्टाफ और प्रशासनिक कर्मचारी) को पारंपरिक शिक्षा की तुलना में कहीं अधिक विविध और जटिल कार्य करने पड़ते हैं। इसी कारण कार्यभार यहाँ एक प्रमुख प्रशासनिक व शैक्षणिक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आता है। जिसमें प्रमुख चुनौती शिक्षार्थी शिक्षक अनुपात, बहुआयामी कार्य जिम्मेदारी, तकनीकी दवाब, समय प्रबंधन की समस्या, भावात्मक एवं मनोवैज्ञानिक दबाव तथा अपर्याप्त स्टाफिंग को एक मुख्य चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है।

3.3.3 निम्न सहभागिता- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। किंतु वास्तविकता यह है कि अनेक संस्थानों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी कम दिखाई देती है। जिसके निम्न कारण दृष्टिगोचित होते हैं जिससे शिक्षार्थी संलग्नता, परामर्श और सहयोग का अप्रभावी क्रियान्वयन, प्रौद्योगिकी की आसान पहुंच, प्रेरणा एवं अनुशासन की कमी, संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग तथा प्रतिधारण दर में गिरावट भी है।

3.4 वित्त नियामक संस्था- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों का संचालन केवल शैक्षणिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वित्तीय और नियामक दृष्टि से भी जटिल होता है। इन संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद और वित्तीय नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होता है। यही स्थिति कई प्रशासनिक चुनौतियों को जन्म देती है लेकिन प्रत्यक्षतः इससे सम्बद्ध चुनौतियों को वर्णित किया गया है।

3.4.1 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लागत को बनाए रखना- मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पूरी तरह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। वर्चुअल क्लासरूम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल कंटेंट, ऑनलाइन परीक्षा और मूल्यांकन सब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से ही संभव है। लेकिन इन सेवाओं को सतत बनाए रखना तथा प्रभावी ढंग से प्रशासनिक स्तर पर प्रबंधित करना जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें मुख्य रूप से वित्तीय स्थिरता, तकनीकी अवसंरचना का रखरखाव, तकनीकी सहयोग, सेवाओं में कमी, डिजिटल विभाजन, साइबर सुरक्षा एवं आंकड़ों का संरक्षण, मानव संसाधन प्रबंध, नवाचार समावेश, गुणवत्ता आश्वासन और नियामक अनुपालन जैसे मुख्य चुनौतियां हैं जो बाध्यता का कारण बनती है।

4. निष्कर्ष:

प्रशासनिक चुनौती न केवल संस्थागत दक्षता को कमजोर करती है बल्कि यह शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के मध्य असंतोष एवं अविश्वास की स्थिति को भी उत्पन्न करती है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का प्रसार, सामाजिक न्याय और समग्र विकास बाधित भी बाधित होता है। दूसरी ओर यदि प्रशासनिक संरचना को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाए तो ये चुनौतियाँ अवसरों में परिवर्तित हो सकती हैं। प्रभावी नेतृत्व, समयबद्ध निर्णय-प्रक्रिया, सतत् प्रशिक्षण, वित्तीय अनुशासन और प्रौद्योगिकी के स्थायी प्रयोग के माध्यम से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं परिणामोन्मुख बनाया जा सकता है।

5. सुझाव:

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की प्रशासनिक चुनौतियों के समाधान हेतु सर्वप्रथम इसकी प्रशासनिक संरचना को पारदर्शी, लचीला और उत्तरदायी बनाया जाना आवश्यक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकेंद्रीकरण से संस्थागत कार्यों की गति और प्रभावशीलता में वृद्धि हो सकती है। तकनीकी दृष्टि से यह अनिवार्य है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण-अधिगम साधनों को सुदृढ़ किया जाए तथा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और ई-लाइब्रेरी को निरंतर अद्यतन एवं सुलभ रखा जाए। साथ ही डिजिटल डिवाइड के अभाव को दूर करने के लिए ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सस्ती और भरोसेमंद इंटरनेट सेवाएँ तथा उपकरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके अंतर्गत शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों

और सहायक कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण एवं क्षमता-विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। कार्यभार का संतुलित वितरण सुनिश्चित करने से कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा और उनकी कार्यक्षमता बनी रहेगी। साथ ही शिक्षार्थी प्रतिधारण और सहभागिता को बढ़ाने के लिए छात्र-केंद्रित नीतियाँ अपनाना आवश्यक है। जिनमें परामर्श, मेंटरिंग, अकादमिक सहयोग, समय पर प्रतिक्रिया तथा प्रेरक गतिविधियाँ शामिल हों और ऑनलाइन फोरम और चर्चा समूह शिक्षार्थियों की सहभागिता को और अधिक सक्रिय बना सकते हैं।

यह भी आवश्यक है कि सरकार, नियामक संस्थाएँ और शैक्षणिक संगठन मिलकर नीतिगत सहयोग और एकरूपता स्थापित करें। औद्योगिक और सामाजिक साझेदारी के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित किया जाए जिससे शिक्षा में समान अवसर और समावेशिता को बढ़ावा मिल सके। यदि इन सुझावों को व्यवस्थित रूप से लागू किया जाए तो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की प्रशासनिक चुनौतियों को न केवल कम किया जा सकता है, बल्कि इस प्रणाली को और अधिक परिणामोन्मुख, स्थायी और गुणवत्तापूर्ण बनाया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य सर्वसुलभ, सर्वसमावेशी और सतत् विकासोन्मुख ज्ञान-व्यवस्था प्राप्त किया जा सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

[1] अवधिया, ए. के., एवं मिगलानी, ए. (2005). मोबाइल लर्निंग: भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए चुनौतियाँ। जर्नल ऑफ़ लर्निंग फॉर डेवलपमेंट, 3(2)। https://doi.org/10.56059/jl4d.v3i2.145

[2] ओवेन्स, आर. जी., एवं वेल्स्की, टी. सी. (2014). ऑर्गनाइजेशनल बिहेवियर इन एजुकेशन: लीडरशिप एंड स्कूल रिफॉर्म। पियर्सन।

[3] बुश, टी. (2007). शैक्षिक नेतृत्व और प्रबंधन: सिद्धांत, नीति, और व्यवहार। साउथ अफ्रीकन जर्नल ऑफ़ एजुकेशन, 27(3), 391–406।

[4] डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट। (2024, 23 जून). भारत की दूरस्थ शिक्षण संस्थाओं का वित्तपोषण: आगे की चुनौतियाँ। डिस्टेंस एजुकेशन – इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। यहाँ से प्राप्त: https://distancelearning.institute/economic-perspective/financing-indias-distance-teaching-challenges/

[5] दास, पी. पी. (2025). भारत में एमओओसी: विकास, नवाचार, प्रभाव और रोडमैप [दृष्टिकोण अध्याय]। arXiv प्रीप्रिंट। यहाँ से प्राप्त: https://arxiv.org/abs/2501.14780

[6] गुज्जरप्पा, एन. एल. एवं चंद्रशेखरा, एम. (2025). ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म का जागरूकता, उपयोग और चुनौतियाँ: एलआईएस शिक्षकों और विद्यार्थियों का एक केस अध्ययन। जर्नल ऑफ़ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, 62(4), 283–293। https://doi.org/10.17821/srels/2025/v62i4/171850

[7] हैलिंगर, पी. एवं ह़ेक, आर. एच. (1996). विद्यालय की प्रभावशीलता में प्रधानाचार्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन: अनुभवजन्य शोध की समीक्षा, 1980–1995। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्वार्टरली, 32(1), 5–44।

[8] हॉय, डब्ल्यू. के. एवं माइकल, सी. जी. (2012). एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन: थ्योरी, रिसर्च, एंड प्रैक्टिस। मैकग्रा-हिल।

[9] क्यूबन, एल. (1988). द मैनेजेरियल इम्परेटिव एंड द प्रैक्टिस ऑफ़ लीडरशिप इन स्कूल्स। ऑल्बनी: एसयूएनवाई प्रेस।

[10] कांबले, ए., गौबा, आर., देसाई, एस., एवं गोल्हार, डी. (Year). प्रशिक्षक-निर्देशित ऑनलाइन लर्निंग वातावरण में परिवर्तन की शिक्षार्थियों की धारणा: कोविड-19 महामारी के दौरान सहायक तत्व और अवरोधक। द इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ़ रिसर्च इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग, 22(1)। https://doi.org/10.19173/irrodl.v22i1.4971

[11] लेथवुड, के., एवं जांट्ज़ी, डी. (2000). संगठनात्मक परिस्थितियों और छात्र सहभागिता पर रूपांतरणात्मक नेतृत्व का प्रभाव। जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, 38(2), 112–129।

[12] मर्फी, जे. (1990). प्रधानाचार्य का शैक्षणिक नेतृत्व। द प्रिंसिपलशिप: कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेज में।

[13] पनिग्राही, एम. आर., एवं मिश्रा, एस. (संपा.) (2022). मुक्त, दूरस्थ और डिजिटल शिक्षा में शोध प्रवृत्तियाँ। ओ. ज़ावाकी-रिक्टर एवं आई. जंग (संपा.), हैंडबुक ऑफ़ ओपन, डिस्टेंस एंड डिजिटल एजुकेशन (पृष्ठ 199–220) में। https://doi.org/10.1007/978-981-19-2080-6_12

[14] शांथिनी, जे. के. (2022). भारत में ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियाँ और अवसर। रीसेंट रिसर्च रिव्यूज़ जर्नल, 1(1), 122–131। https://doi.org/10.36548/rrrj.2022.1.011

[15] वानी, एस. ए., असगर, ए., एवं श्रीवास्तव, एम. (2023). जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में दूरस्थ उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षार्थी सहायता सेवाएँ। एशियन एसोसिएशन ऑफ़ ओपन यूनिवर्सिटीज जर्नल, 18(3), 246–261। https://doi.org/10.1108/aaouj-02-2023-0026

Cite this Article:

राहुल यादव एवं डॉ० देवेंद्र कुमार यादव, "दूरस्थ शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की चुनौतियाँ: वैचारिक अंतर्दृष्टि", *Naveen International Journal of Multidisciplinary Sciences (NIJMS), ISSN: 3048-9423 (Online), Volume 2, Issue 1, pp. 100-106, August-September 2025.*

Journal URL: https://nijms.com/

DOI: *https://doi.org/10.71126/nijms.v2i1.92*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.